आशुलिपिक ग्रेड II	3
दूरसंचार कार्यालय सहायक	137
लेखा अधिकारी	2
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5
जोड़ :	439

(खंड) उपर्युक्त तर्कसंगत पदों में से 175 पद सृजित किए जा चुके हैं।

(निदेशक दूरसंचार,	4
निदेशक लेखा	2
मण्डल इंजीनियर	2
कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी	97
केबल सप्लाईसर	38
मोटर ड्राइवर	14
समूह "घ"	9
अ० श्रे० लि०/उ० श्रे० लि०	9)

(ग) और (घ) : 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार देश में प्रति एक हजार टेलीफोनों के लिए नियोजित कर्मचारियों की संख्या 83 है। यह संख्या विश्व के लगभग सभी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है जहां यह संख्या 5 से 30 के बीच है। विभाग, नेटवर्क में आधुनिक प्रौद्योगिकी अधिष्ठापित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है जिससे कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाएगी और साथ ही स्टाफ की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा स्टाफ को प्रशिक्षित तथा पुनः प्रशिक्षित की जरूरत भी नहीं होगी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए, नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या स्थिर हो गई है और नए पद मार्ग निर्देशानुसार सेवा निवृत्ति आदि के कारण मौजूदा स्टाफ में हुई कमी की सीमा तक ही स्वीकृत किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

2201. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों का विकास/आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) :

(क) जी हां।

(ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में अधिकांशतः इलेक्ट्रानिक उपस्कर द्वारा लगभग 1,75,000 लाइनों को बदलना। उन्हें आटोमेटिक बनाने के अतिरिक्त लगभग 5,30,000 लाइनों की वृद्धि किए जाने पर विचार किया गया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं :

— मार्च, 1994 तक नेटवर्क को पूरी तरह आटोमेटिक बनाना

— मियाद समाप्त और जीर्ण-शीर्ष उपस्करों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाना

— 8वीं योजना अवधि के दौरान व्यवहारिक रूप से सभी डिजिटल

किस्म के नए उपस्कर शामिल किया जाना

— डायरेक्टरी पूछताछ बिल प्रणाली मैनुअल ट्रंक सेवा आदि जैसी दूर-संचार सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण

— सभी स्ट्रोजर एमएएक्स-3 एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना

— सभी एक्सचेंजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के भाग के रूप में

— सभी एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करना

— यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

Relief for Telephone Subscribers

2202. DR. SANJAYA SINH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had announced a number of facilities for the Telephone Subscribers, recently, as per the newsitem entitled : "Relief on telephone not working", which appeared in the Hindustan Times, dated 3rd October, 1992; and

(b) if so, what are the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) Following facilities for the telephone subscribers were announced by the Minister of State for Communications.

(i) For telephone subscribers whose telephone services remain interrupted/ suspended continuously for more than 14 days due to departmental reasons, full month's rental would be waived.

(ii) Wherever Telephone Directories have not been published, the Directory Inquiry service 197 would be available without any charge.

(iii) Subscribers would be allowed to use their own telephone instrument.

(iv) STD/ISD Public Call Offices would be sanctioned to unemployed youths under liberalised policy.

Postal Employees on Strike in Madurai

2203. SHRI V. GOPALASAMY :
SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the postal employees, of Madurai in Tamilnadu observed a sit-in-strike;

(b) if so, what were their demands; and

(c) what decision Government have taken on their demands ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir. A large number of postal employees in Madurai City participated in sit-in-strike from 26-10-92 to 1-11-92.

(b) Some local unions demanded that proposed re-organisation of Madurai Moffusil, Dindigul and Madurai City Divisions should not be implemented till specific proposals for alternative re-organisation of postal divisions submitted by them are examined/accepted.

(c) The Government have since implemented orders regarding re-organisation of postal services in three divisions w.e.f. 1-12-92.

Non Receipt of acknowledgement due cards by senders

2204. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Acknowledgement Due Card of Registered letters/ covers are not returned to the senders after delivery of the Registered letters/covers; and

(b) if so, what are the details in this ragard and what steps Government propose to ensure that the Acknowledgement Due Card certainly reaches the senders after their delivery to the addresses ?